(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps Government are taking to improve the deteriorating moral tenor of sponsored TV programmes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) and (b) Yes, Sir. The Directorate of Field Publicity and Song and Drama Division are proposed to be merged because it is proposed that they should now do concentrated publicity in a few selected areas and it is felt that for this changed pattern of activity, it would be desirable to merge the two organisations. The merger is aimed at improving their effectiveness and at the same time curtail expenditure.

(c) While it is not corect to say that there is deterioration in moral tenor of sponsored programmes, review of content and format is a continuous process in Doordarshan and vigil is kept on quality of the programmes.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विभागीय समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि

376. **श्री अच्छे लाल बाल्मीक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी, ट्रांसफर एवं पोस्टिंग से संबंधित कमेटी और विभागीय पदोन्नति कमेटी में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का कोई प्रतिनिधि रखा जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कनिष्ठ अभियन्ताओं और ऊंचे पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की कुल कितनी बैठकें हुई और उनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के किस-किस अधिकारी को प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां, जहां भी यह लागू होता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 31

इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के नाम नीचे दिए गए हैं : --

सर्वश्री	अनुसूचित जनजाति
1. के. किषगेन,	अनुसूचित जाति
2. एस. पी. विस्वास	तदैव
3. काशी राम	तदैव
4. फूल सिंह	तदैव
5. एम. एम. दास	तदैव

पटना में हुडको का कार्यालय

377. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में हुडको की एक शाखा एक निजी भवन में खोली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका कितना किराया देना पड़ रहा है ; और

(ग) किराये का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 6,500 रुपये प्रतिमाह ।

(ग) उप मण्डलीय अधिकारी व आवास नियंत्रक, पटना द्वारा जारी किए गए "उचित किराया प्रमाण पत्र" के आधार पर मासिक किराया निर्धारित किया गया है ।